उपसंहार

आजादी के बाद नेहरू सरकार के कंधों पर देश के विकास की जिम्मेदारी थी। इसके लिए सरकार को बहुउद्देशीय बाँध परियोजनाओं के निर्माण की जरूरत महसूस हुई। बाधों के निर्माण से देश की बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता था। बाँधों से यह भी लाभ था कि नए खुलने वाले उद्योग धंधों को पानी उपलब्ध कराया जा सके, जल संकट वाले क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति की जा सके एवं देश में फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सके आदि।

आरंभिक दौर में इन बहुउद्देशीय बाँध परियोजनाओं को बहुत अधिक विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि उस दौर में कहीं न कहीं देश की जनता में ये भावना रही है कि उन्हें देश के विकास के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। बाँधों के निर्माण के लिए जमीनों का अधिग्रहण करने वाली सरकारें भी यही मानती रहीं कि सामूहिक हित की खातिर कुछ लोगों को त्याग तो करना चाहिए। जैसे-जैस जनता बाँधों परियोजनाओं के दुष्प्रभावों से परिचित होती गई। इनका विरोध तीव्र होता गया।

इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं से स्थानीय जनता को होने वाला लाभ नगण्य था और सबसे ज्यादा दुष्प्रभावों का सामना इन्हें ही करना पड़ा। परियोजनाओं के अधिकांश विस्थापितों को दी जाने वाली जमीन और मुआवजा पर्याप्त नहीं था। साथ ही मूल जीवन परिस्थितियों से भिन्न वातावरण में रहने के कारण आर्थिक, सांस्कृतिक क्षति और मानसिक विलगाव का सामना करना पड़ा।

स्थानीय जनता के अलावा बड़े-बड़े वैज्ञानिक, पर्यावरणविद् एवं सामाजिक कार्यकर्ता भी समय-समय पर बड़े बाँधों के निर्माण पर सवाल उठाते रहे हैं। बड़े बाँधो से बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित प्रभावित होते हैं । देश भर में जनता बड़े बाँधों के खिलाफ़ आंदोलनरत है। सबसे अधिक चर्चित बाँध विरोधी आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन रहा है जिसकी नेता मेधा पाटेकर हैं। टिहरी बाँध से प्रभावित लोग अभी भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं।

एक लोकतांत्रिक समाज बचाए रखने में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसे लोकतंत्र का चौथा आधार भी कहा जाता है। टिहरी बाँध आंदोलन के दौरान कई पत्र-पत्रिकाओं ने इसे स्थान दिया। विशेषकर

स्थानीय स्तर के समाचार पत्रों ने टिहरी बाँध आंदोलन के प्रभावितों के पक्ष को सामने लाया। हालाँकि बाँध समर्थकों का पक्ष भी मीडिया में सामने आता रहा लेकिन उसका प्रतिशत कम ही रहा।

मीडिया ने टिहरी बाँध प्रभावित जनता एवं आंदोलनकारियों के कई मुद्दों और समस्याओं को उठाया। मीडिया के सहयोग से इस आंदोलन की गति को प्रोत्साहन मिलता रहा। मीडिया की भूमिका के बहुत सारे पहलू होते हैं जैसे कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय मीडिया। राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया की भूमिकाएं अलग-अलग हैं। स्थानीय स्तर पर खबर आती है तो एक छोटी घटना को लेकर भी चर्चा हो सकती है जबकि राष्ट्रीय स्तर उस मुद्दे के विभिन्न पक्षों पर बात की जाती है। संसाधनों की कमी के बावजूद स्थानीय मीडिया ने टिहरी बाँध आंदोलन को गति देने में मदद की है।

शोधार्थी को शोध कार्य के दौरान प्रश्नावली के ज़रिए किए अध्ययन से ज्ञात हुआ कि कि टिहरी बाँध आंदोलन के दौरान सर्वाधिक भूमिका स्थानीय मीडिया की रही। स्थानीय समाचार पत्रों 'युगवाणी' और 'नैनीताल समाचार' की खबरों का विश्लेषण करने पर पता चला कि 75% खबरें बाँध आंदोलन के पक्ष में है। इस दौरान आंदोलन के विपक्ष में मात्र 12.5% खबरें हैं उतनी ही 12.5% खबरें मुद्दे के प्रति तटस्थ हैं।

लिंगगत आधार पर आंदोलन से संबंधित खबरों का विश्लेषण करने पर पाया कि 50% खबरें ऐसी हैं जिनमें किसी जेंडर का जिक्र नहीं आया है। 25% खबरें ऐसी हैं जिनमें महिलाओं एंव पुरुषों दोनों की भागीदारी बताई गई है। 25% खबरें ऐसी हैं जिनमें केवल पुरुष आंदोलनकारियों का जिक्र है। ऐसी खबरों का प्रतिशत शून्य है जिनमें सिर्फ महिलाओं की भूमिका बताई गई हो। अत: स्पष्ट होता है कि महिला आंदोलनकारियों को सिर्फ 25% स्थान मिल पाया है जबकि पुरुष आंदोलकारियों को 50 प्रतिशत।

समाचार पत्रों में बाँध संबंधी विभिन्न समस्याओं को उठाया गया है। 87.5% खबरों में इन समस्याओं का जिक्र किया गया है। 12.5% में समस्या का कोई जिक्र नहीं केवल आंदोलन की गतिविधियों को बताया गया है। खबरों में टिहरी बाँध से संबंधित विभिन्न मुद्दे आए हैं जैसे पर्यावरणीय पहलू, विस्थापन की समस्या, पुनर्वास की मांग, रोजगार की समस्या। बाँध प्रशासन द्वारा आंदोलनकारियों के साथ कि गए व्यवहार का चित्रण जैसे- पुलिस लाठीचार्ज, आंदोलनकारियों से भरी बस का दुर्घटनाग्रस्त करवाया जाना, द्वारा आंदोलनकारी जनता को विभिन्न तरीकों से आंदोलन खत्म करने के लिए दबाव बनाना आदि। बाँध समर्थकों की ओर से आंदोलन को कमजोर करने के लिए इसका चेहरा रहे सुंदरलाल बहुगुणा की छवि को प्रभावित करने की कोशिशें की गईं।

प्रभावित जनता का मानना है कि आंदोलन के दौरान मीडया की भूमिका मिली-जुली रही है। बहुमत की बात करें तो अधिकाँश लोगों ने माना है कि स्थानीय मीडिया की इसमें ज्यादा अहम भूमिका रही है।

सुंदरलाल बहुगुणा की लगातार सक्रियता और आंदोलन के नेता के तौर पर भी खबरों में सर्वाधिक उनका नाम आया है। आंदोलन का चेहरा रहे सुंदरलाल बहुगुणा की लोगों के बीच पर्यावरणविद की छवि अधिक रही है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का भी चर्चित चेहरा रहे हैं।

टिहरी क्षेत्र की अधिकांश जनता बाँध के विरोध में रही है। जो लोग बाँध के पक्ष में या तटस्थ थे वे भी पुनर्वास की स्थितियों से असंतुष्ट हैं। विस्थापन के बाद अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई है। ऐसे लोगों की संख्या कम है जिनकी स्थिति में सुधार आया हो। बाँध निर्माण के फायदों के सबंधं में अधिकांश लोगों का मानना है कि किए गए वादों के मुताबिक उनको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि उन्हें नुकसान ही अधिक उठाना पड़ा।

प्रश्नावली के ज़रिए निकले निष्कर्ष के मुताबिक सर्वाधिक लोगों का मानना है कि महिलाओं की आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अधिक रही है। जबकि खबरों का विश्लेषण करने पर पाया गया है कि मात्र 25 प्रतिशत खबरों में महिलाओं की भागीदारी की का जिक्र है। अखबारों में महिलाओं को उनकी भागीदारी के मुकाबले उचित स्थान नहीं मिल पाया है।

विकास के मुद्दे पर बनी टिहरी बाँध परियोजना अपने उद्देश्यों का पूरा नहीं कर पाई रही है। टिहरी बाँध के विस्थापित मानसिक रूप से विलगाव भी महसूस करते हैं। पूरी तरह से कभी किसी का पुनर्वास हो ही नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति अपने परिवेश से जुड़ा होता है।

लोगों का मानना रहा है कि आंदोलन के कमज़ोर होने का कारण रहा कि आंदोलनकारी खुद ही कमजोर पड़ गए हालांकि इसका एक कारण प्रशासनिक दमन भी रहा है। लगभग तीन दशकों सक्रिय तौर पर चले टिहरी बाँध विरोधी आंदोलन पर एक मत यह भी आता है कि बाँध तो रुका नहीं, इसका फिर क्या लाभ हुआ। लेकिन टिहरी बाँध आंदोलन, नर्मदा बचाओ जैसे आंदोलनों से बड़े बाँधों के खिलाफ़ एक बहस को जन्म दिया और इसके औचित्य पर सवाल उठाया। बाँध संबंधी मुद्दों की बहस को व्यापक रूप में देने में मीडिया की भी अहम भूमिका रही है।